महत्वपूर्ण एवं खास

खड़ी कार में लगी भीषण आग, मारुती की स्विफ्ट जलकर खाक

धमतरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के धमतरी में खड़ी कार में भीषण आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. आस-पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के धमतरी में खड़ी कार में भीषण आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. आस-पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

बिजली खंभे के सपोर्ट तार में था करंट, झुलस गई 16 साल की लडक़ी, मौके पर ही मौत

भिलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रिक पोल की स्टे तार की चपेट में आने से 16 साल की लडक़ी की मौत हो गई। मौत के बाद से मोहल्ले में रोष है। भिलाई तीन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार, भिलाई के सेक्टर -1 कॉलोनी में रहने वाले मिंटू शील की बेटी विनीता शील विनीता 10वीं की परीक्षा दे रही थी। बुधवार की दोपहर वह अपने घर के पास दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते-खेलते उसने अचानक बिजली के पोल में लगे स्टे तार को पकड़ लिया। तार में करंट होने के कारण वह पोल से चिपक गई। जब लोगों ने उसे देखा तो बचाने के लिए दौड़े, जब तक वे वहां पहुंचे तब तक लडक़ी बुरी तरह झुलस गई थी और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही भिलाई तीन पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद कराकर शव को वहां से हटाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।

रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 50 हजार नगदी सहित जेवर पार

कोरबा (आरएनएस)। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कुकरीचोली निवासी सीएसईबी के रिटायर्ड कर्मचारी के खेत से घर लौटने पर सामान बिखरा मिला। चोरों ने घर में रखे 50 हजार नगदी समेत सोने.चांदी के आभूषण को पार कर दिया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई है। ग्राम कुकरीचोली निवासी जोसेफ कुजूर व उसकी पत्नी रीना कुजूर 22 मार्च सुबह करीब 9 बजे घर पर ताला लगाकर गांव में ही अपने खेत की ओर गए थे। इसकी भनक चोरों को लग गई और सूने मकान में दिनदहाड़े घुसकर घर के बेड के नीचे रखे 50 हजार नगदी समेत सोने-चांदी के आभूषण पार कर दिया। दोपहर 12.30 बजे खेत से घर पहुंचे दंपति को सामान बिखरा मिला। घर में चोरी होने की सूचना उरगा थाना में दी।

10वीं, 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण शिक्षित युवाओं के लिए 27 को प्लेसमेंट कैम्प

रायपुर (आरएनएस)। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 मार्च को स्थान जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर में सुबह 11 बजे से शाम 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से उमादेवी बहुउद्देशीय शिक्षा एवं विकास संस्थान, रायपुर, रेसीलेंट इनोवेशन प्रायवेट लिमिटेड, गुरुग्राम (हरियाणा) एवं बजाज फायनेंस लिमिटेड, रायपुर द्वारा डी.टी.पी. ट्रेनर, सिलाई ट्रेनर, मोबीलाईजर, कार ड्रायवर, सेल्स एक्सीक्यूटीव एवं सेल्स ऑफिसर के 68 पदों पर भर्ती की जाएगी।इन पदों के लिए 10वी,12वीं, स्नातक, कम्प्यूटर एवं सिलाई में डिप्लोना उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की जाएगी।भर्ती उपरांत 8 से 15 हज़ार रूपये प्रतिमाह की दर पर भुगतान किया जाएगा।प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित हो सकते है।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज का लोकार्पण

- रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर प्रदेश का पहला फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज
- 28.11 करोड़ रुपए की लागत से बना है फुल हाईट वाल्टियर रेल लाइन अंडर ब्रिज'
- शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी होगी लाभान्वित'

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर - विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाईट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है जिसे 28.11 करोड़ रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

इस फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था और आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई पहुंच मार्ग स्थित 336.96 मीटर है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के यातायात को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। इस दौरान 9 रेलवे ओवर ब्रिज और 6 अंडर ब्रिज के कार्य पूरे किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से अधोसंरचनाओं का निर्माण किया है। हमारी मजबूत अधोसंरचना और मजबूत अर्थव्यवस्था के तालमेल से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के नये आयाम स्थापित करेगा।

रेलवे अंडर ब्रिज के लोकार्पण अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर ऐजाज ढेबर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

27 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित, शासन की योजना के तहत की गई अनुशंसा

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक
- अब तक 128 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित
- शासन की योजना का लाभ लेकर अनाधिकृत निर्माण को करा सकते है वैध
- 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, उससे अधिक होने पर क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित की गई है राशि

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में आवासीय एवं गैर आवासीस अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़ निवेश क्षेत्र अंतर्गत 25 आवासीय एवं 2 गैर आवासीय प्रकरणों सहित कुल 27 प्रकरणों के नियमितीकरण (वैध करने)हेतु अनुशंसा की गई। इसके पूर्व 101 अनाधिकृत निर्माण नियमित किये गये है। इस प्रकार अब तक कुल 128 अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया गया है।

अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 लागू किया गया है। इस नियम के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए भवन मालिकों को नगर निगम कार्यालय के भवन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ कागजात जैसे खसरा बी-1, बी-2, भवन अनुज्ञा आदि भी जमा करना होगा। अब तक प्राप्त नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रकरण बनाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजा गया। जिसके पश्चात इन प्रकरणों पर समिति की बैठक में निर्णय लेकर नियमितीकरण (वैध घोषित करने) की कार्यवाही की गई।

प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनाधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किन्तु 120 वर्ग मी.से 240 वर्ग मी.क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्डों के नियमितीकरण तथा भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी मापदण्ड निर्धारित किए गए है।

नियमितीकरण के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क

नियमितीकरण से संबंधित जानकारी लेने एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए निगम के उप अभियंता मुन्ना ओझा मोबा.नंबर 7389810253, सहायक अभियंता सूरज कुमार देवांगन मोबा.नं.87702-86364 एवं लिपिक प्रदीप तिवारी 7987112918 पर संपर्क कर सकते हैं।

गोधन न्याय योजना को मिला एक और राष्ट्रीय अवार्ड

- नई दिल्ली में 25 मार्च को मिलेगा सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को फिर से एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस योजना को 20वां कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट गुरप ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसके लिए प्रदेशवासियों एवं कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं है।

यह अवार्ड 25 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलीजी के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागृह में दिया जाएगा। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट केटेगरी में चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में ''स्कॉच गोल्ड अवार्ड'' और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड'' भी मिल चुका है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत

जगदलपुर (आरएनएस)। दो दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया गया। सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री शाह की अगवानी पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, लच्छूराम कश्यप, डॉ सुभाऊ कश्यप, वन विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी, पूर्व महापौर किरण देव, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव, पूर्व सदस्य संग्राम सिंह राणा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा सहित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियोंद्वारा की गई।

उत्कल एक्सप्रेस में बीमार बुजुर्ग महिला की मौत, बिलासपुर में उतारा शव

बिलासपुर (आरएनएस)। ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग बीमार महिला की मौत हो गई। शव को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतारा गया। स्टेशन मास्टर से मेमो मिलने के बाद जीआरपी पहुंची।

लेकिन, स्वजनों के निवेदन पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसके बाद स्वजन शव को लेकर ओडिशा के लिए रवाना हो गए।

घटना गुरुवार सुबह की है। इस ट्रेन के एस-4 कोच में ओडिशा झारसुगुड़ा का एक परिवार यात्रा कर रहा था। वह हरिद्वार गए थे। वहां से लौट रहे थे। तभी परिवार के सदस्यों में शामिल 60 वर्षी महिला की तबीयत बिगडऩे लगी। सांस फूलते देख स्वजन घबरा गए।

उन्होंने चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए टीटीई से मदद मांगी। टीटीई ने कंट्रोल को जानकारी दी। जिसके बाद रेलवे अस्पताल से चिकित्सक भेजा गया। चिकित्सक ट्रेन के पहुंचने से पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म एक पर आकर खड़ी हुई। रेलवे अस्पताल के चिकित्सक ने जांच की।

जांच के दौरान उन्होंने महिला के मृत होने की पुष्टि की। इस पर स्वजन घबरा गए। शव ट्रेन में लेकर नहीं जा सकते थे। इसलिए स्टेशन मास्टर ने स्वजनों को जानकारी दी कि शव को यहीं उतारना पड़ेगा। यह नियम भी है। लिहाजा रेलवे ने शव को उतारा। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को मेमो भेजकर इस घटना के संबंध में जानकारी दी। जीआरपी मौके पर पहुंची। पंचनामा के बाद जीआरपी पोस्टमार्टम भी कराती।

लेकिन, जैसे ही स्वजनों को जानकारी मिली वह मायूस हो गए। उन्होंने बार- बार जीआरपी से निवेदन किया कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वैसे भी मृतिका बुजुर्ग के साथ बीमार भी थी। उनके निवेदन के आधार पर ही जीआरपी ने पोस्टमार्टम नहीं कराने का आश्वासन दिया। वहीं स्वजनों के निवेदन पर शव को ओडिशा लेकर जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराई। इसके बाद शव को लेकर स्वजन झारसुगुड़ा के लिए रवाना हो गए।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने केडार, किंकारी और आमाकोनी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने निरीक्षण किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले के किंकारी, केडार और पुटका मध्यम सिंचाई जलाशयों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से गुरूवार को निरीक्षण किया। सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम केडार, भडीसार, आमाकोनी और बरमकेला विकासखंड के किंकारी जलाशय का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को किंकारी जलाशय में जल संसाधन विभाग और मनरेगा से कार्य कराने के निर्देश दिए। जलाशय क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए मणिकंचन केन्द्र खोलने की सहमति दी है। जलाशय के समीप शिव मंदिर है, जहां ओडिशा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। कलेक्टर ने वहां कार्यरत ग्रामीणो से कार्य के बारे में बातचीत की। अधिकारियों ने कलेक्टर को जानकारी दी कि इस जलाशय से 36 गांवों के किसानों को सिंचाई होती है। कलेक्टर ने कलमा बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बैराज में जल की वर्तमान स्थिति, जल का उपयोग आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरे में एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा और कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि बरमकेला विकासखंड के अमूर्रा जलाशय के बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है। बोइरमाल जलाशय कार्य का नहर मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। किंकारी मध्यम सिंचाई जलाशय को जीर्णोद्धार के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित करने, गार्डनिंग और लाइटिंग आदि के लिए केन्द्रीय जल संसाधन विभाग को 11 करोड़ का डीपीआर भेजा जा चुका है। इसी प्रकार झोरझोटा लघु सिंचाई जलाशय के लिए 3 करोड़ का कार्य प्रस्तावित है। किंकारी मुख्य नहर अंतर्गत ग्राम अमोदा, रिसोरा, बड़े नवापारा और खैरगढ़ी के नहर मरम्मत कार्य प्रस्तावित है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी टाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री बघेल ने की है एक एकड़ में अब 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर
- गांव के किसानों ने कहा अब धान की बिक्री और बोनस दोनों में फायदा मिलेगा

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। उन्होंने कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान जहां भी गया किसानों की एक ही मांग थी, समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए। किसानों के मांग अनुरूप धान की बिक्री सीमा 15 क्ंविटल से बढ़ाकर अब 20 क्ंविटल कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई इस घोषणा से जिले के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ के किसानों में बेहद खुशी है। किसानों की ऋण माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सशक्त बनाया। कभी हमने सोचा नहीं था कि गोबर एवं गौमूत्र बेचकर भी इसका फायदा उठायेंगे। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा को सुनकर सभी किसानों ने मुख्यमंत्री को अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है।

ग्राम-जुर्डा के किसान ललित राठिया ने बताया कि वे अपने 5 एकड़ भूमि में धान एवं सब्जी फसल की खेती करते है। मुख्यमंत्री ने जब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की तो सुनकर बेहद खुशी महसूस हुई। क्योंकि 15 क्ंविटल धान बेचने के बाद हमारे पास धान बच जाता था, जिसको हमें औने-पौने दामों में बेचना पड़ता था। जिससे काफी नुकसान होता था। ग्राम-सकरबोगा के किसान दुखीराम सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब इससे हम पूरा धान की बिक्री कर सकेंगे और हमें बोनस का भी फायदा मिलेगा। इसी तरह कृषक नवीन सिदार शासन के इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार खेती-किसानी पर निर्भर है। वे अपना पूरा धान सहकारी समिति में विक्रय करते है। उनका कहना था कि 15 क्ंविटल धान बेचने के बाद धान बच जाता था। जिसको घर में रखने से परेशानी होती थी या तो बचे धान को कम कीमत पर बेचना पड़ता था। जिसकी वजह से काफी नुकसान होता था, वहीं बोनस का लाभ भी नहीं मिल पाता था।